'विकसित भारत' के मूल में कृषिः सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा

अनिल कुमार एसजी
संस्थापक, समुन्नति

भारत जैसे-जैसे विकसित भारत के 2047 के विजन की ओर बढ़ रहा है- एक ऐसा भविष्य जो आत्मनिर्भर राष्ट्र और समावेशी विकास से चिह्नित हो- कृषि इस परिवर्तन में सबसे आगे है। भारत की आधी जनसँख्या खेती पर निर्भर है और कृषि जीडीपी में लगभग 18 प्रतिशत का योगदान देती है, यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, रोजगार उत्पन्न करने और आर्थिक उन्नति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

हाल के वर्षों में कृषि की भूमिका पारंपरिक सीमाओं से आगे निकल गई है। अब इसमें पर्यावरणीय स्थिरता, ग्रामीण विकास और तकनीकी नवाचार के लक्ष्य सम्मिलित हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि विकास न केवल समावेशी हो बल्कि लचीला भी हो। विकसित भारत के संदर्भ में, खाद्य सुरक्षा केवल जनसँख्या को खिलाने के बारे में नहीं है- यह राष्ट्र निर्माण के बारे में है। विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने में कृषि की क्षमता को पर्याप्त रूप से साकार करने के लिए, जमीनी स्तर पर संरचनात्मक सुधार और सहयोगात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), सामूहिक कृषि व्यवसाय (सीबीबीओ) और अन्य सहकारी समितियों जैसे सामूहिक संगठनों के विभिन्न रूपों के माध्यम से किसानों का सामूहिकीकरण, छोटे किसानों की आजीविका को बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली रणनीति के रूप

में उभरा है। सामूहिकीकरण की शक्ति का लाभ उठाकर, वे कई चुनौतियों को पार कर सकते हैं और अधिक समृद्ध और टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ): विकास के इंजन

इस दृष्टि को सहायता देने वाली परिवर्तनकारी पहलों में से एक किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का पारिस्थितिकी तंत्र है। ये अर्थव्यवस्था में वृद्धि कर रहे हैं, सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ा रहे हैं और आधुनिक, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। वे बिचैलियों पर निर्भरता को भी कम करते हैं, औपचारिक ऋण तक पहुँच को सक्षम करते हैं और किसानों को संस्थागत खरीददारों को सीधे बेचने की अनुमति देते हैं। इस प्रकार, एफपीओ ग्रामीण आर्थिक सशक्तीकरण की रीढ़ बनते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक किसान भारत की विकास यात्रा का सहभागी बने।

ये प्रयास केवल समाधान प्रदान करने के बारे में नहीं हैं - वे एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के बारे में हैं जहाँ सभी हितधारक फलते-फूलते हैं। वित्त, बाजार पहुँच और सलाहकार सहायता में अंतर को पाटकर, वे किसानों के लिए उच्च आय, सुदृढ, अधिक लचीले किसान समूह, कुशल मूल्य श्रृंखलाएं सक्षम कर रहे हैं जो अपव्यय को कम करते हैं और लाभप्रदता को अधिकतम करते हैं और भारत के लिए एक स्थायी कृषि भविष्य बनाते हैं। अपने किसान-प्रथम दृष्टिकोण और स्केलेबल प्रभाव मॉडल के साथ, यह भारत में कृषि के संचालन की विधि को पुनरू परिभाषित कर रहा है - यह सुनिश्चित करता है कि विकास और समृद्धि की यात्रा में कोई भी छोटा किसान पीछे न छूटे।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि एफपीओ जैसी पहल दीर्घकालिक प्रभाव प्रदान करती हैं, उन्हें टिकाऊ कृषि प्रथाओं और प्रौद्योगिकी-संचालित नवाचारों द्वारा सुदृढ़ किया जाना चाहिए। टिकाऊ प्रथाओं और एआई उपकरणों को एकीकृत करने से उत्पादकता, लचीलापन और किसान सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर तेजी से विकसित हो रही कृषि-अर्थव्यवस्था में पनपने के प्रयासों को सुदृढता मिलती है।

संधारणीय कृषि पद्धतियाँः दीर्घकालिक विकास की कुंजी

भारत की कृषि क्षमता को अनलॉक करने के लिए दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। खंडित भूमि जोत मापनीयता और मशीनीकरण में बाधा डालती है, जो भारतीय कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। वैश्विक बेंचमार्क की तुलना में उत्पादकता कम बनी हुई है। जलवायु भेद्यता, पानी की कमी और अनियमित मानसून आय स्थिरता को कमजोर करते हैं। अपर्याप्त मूलभूत संरचना के कारण फसल कटाई के बाद बहुत अधिक हानि होती है और कई किसानों के पास कम मूल्य के ऋण तक पहुँच नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, रासायनिक इनपुट के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी का क्षरण हुआ है, जिससे दीर्घकालिक उत्पादकता प्रभावित हुई है।

इन चुनौतियों से पार पाने और 'विकसित भारत' के विजन को साकार करने के लिए, भारत को दीर्घकालिक विकास के लिए संधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा। फसल चक्र, जैविक खेती और सटीक सिंचाई जैसी पद्धतियाँ मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं, पानी का संरक्षण करती हैं और जैव विविधता को बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा, संधारणीय पद्धतियाँ ग्रामीण समुदायों की लचीलापन को सुदृढ करेंगी, जिससे वे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए उन्नत विधियों से अनुकूल हो सकेंगे। इसलिए, भारत को जल-कुशल सिंचाई और सूखा-रोधी फसलों के माध्यम से जलवायु स्मार्ट कृषि पहलों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, मिट्टी और जैव विविधता की रक्षा के लिए प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए किसानों की बाजारों तक पहुँच में सुधार करना, बीमा और अनुदान जैसे सुलभ ऋण और वित्तीय उपकरण प्रदान करना, और कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग और कटाई के बाद की तकनीकों में निवेश के साथ ग्रामीण मूलभूत संरचना को सुदृढ करना।

एआई-आधारित नई तकनीकः भविष्य के लिए कृषि को बदलना

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय कृषि में क्रांति लाने और मौसम (अप्रत्याशित मौसम) से लेकर मंडी (बाजार में उतार-चढ़ाव) तक कई चुनौतियों का सामना कर रहे भारतीय किसानों को सशक्त बनाने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है।

वैश्विक और भारतीय कृषि दोनों में एआई का एकीकरण कई तरह के अनुप्रयोगों को सम्मिलित करता है, जिसमें कीट और खरपतवार का पता लगाना, कृषि रोबोटिक्स, ड्रोन का उपयोग करके फसल स्वास्थ्य मूल्यांकन, पूर्वानुमान विश्लेषण के माध्यम से सटीक खेती और एआई-संचालित फसल मूल्य पूर्वानुमान सम्मिलित हैं। ये प्रगति न केवल खेती की विधियों को बदल रही है, बल्कि दक्षता और स्थिरता के लिए नए मानक भी स्थापित कर रही है।

एक उल्लेखनीय उदाहरण पूर्वानुमानित रखरखाव (PDM) के लिए तकनीक है, जो सेंसर और मापने वाले उपकरणों का उपयोग करके उपकरणों से संकेतों के आधार पर स्वचालित रूप से रखरखाव शुरू करती है। सटीक कृषि में, PDM फसल के स्वास्थ्य, पोषक तत्वों के स्तर, रोग प्रसार और जलवायु स्थितियों के बारे में अमूल्य वास्तविक समय की सूचना देता है।

आवश्यक है कि ए.आई. को सभी समस्याओं के समाधान के स्थान परएक उकरण के रूप में देखा जाये। उपग्रह इमेजरी जैसी तकनीकों के साथ प्रासंगिक डेटा, खेती की विधियों और स्थानीय परिस्थितियाँ होनी चाहिए ताकि उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके। इसलिए, ए.आई. के अधिकतम लाभ के लिए इसे चरणबद्ध और समुदाय-सम्मिलित अपनाने की रणनीति महत्वपूर्ण है।

आगे बढ़नाः कृषि के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण

भारत का कृषि क्षेत्र एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल से गुजर रहा है, जो सरकार द्वारा स्थिरता और प्रौद्योगिकी एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने से प्रेरित है। यह बदलाव 2047 तक 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने, उत्पादकता में सुधार करने और किसानों की आजीविका को बढ़ाने के लिए कई सरकारी पहल आरम्भ की गई हैं।

पीएम-कुसुम का उद्देश्य सौर सिंचाई को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना है। सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) जलवायु-स्मार्ट कृषि (सीएसए) प्रथाओं को बढ़ावा देता है, जिससे किसान जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हो सकें और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार कर सकें, कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और नीति आयोग द्वारा आरम्भ किया गया आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी), कृषि और जल प्रबंधन सहित आकांक्षी जिलों में सामाजिक-आर्थिक परिणामों को उन्नत बनाने पर केंद्रित है। एडीपी के अन्तर्गत एक प्रमुख पहल किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना है, जो संसाधनों, बाजारों और प्रौद्योगिकियों तक पहुँच प्रदान करके छोटे किसानों को सशक्त बनाते हैं।

विकसित भारत 2047 की ओर भारत की यात्रा उसके कृषि क्षेत्र के समावेशी और सतत विकास पर निर्भर करती है। रणनीतिक निवेश, किसान-केंद्रित नवाचारों और सरकार, निजी खिलाड़ियों और स्टार्टअप के बीच सहयोगी भागीदारी के साथ, कृषि राष्ट्रीय परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बन सकती है।

सतत चुनौतियों का समाधान करके और स्थिरता, मूलभूत संरचना और प्रौद्योगिकी में अवसरों को अपनाकर, भारत एक ऐसा कृषि पारिस्थितिकी तंत्र बना सकता है जो न केवल उत्पादक और लचीला हो, बल्कि न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार भी हो। अपने किसानों को सशक्त बनाकर, भारत अपने भविष्य को सशक्त बनाता है- और एक सच्चे विकसित राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त करता है।